

शिक्षा पर कान नहीं, रोजगार पर ध्यान नहीं! कोरे आश्वासन से कॉलेज चलाएंगे खट्टर और रामबिलास

विवेक की नेहरू कॉलेज पर विशेष रिपोर्ट

कहां है शिक्षा मंत्री राम बिलास शर्मा! नेहरू कॉलेज की मुख्य इमारत जर्जर अवस्था में पड़ी है। प्रिंसिपल ऑफिस और अधिकांश क्लास रूम भी इसी इमारत में चल रहे हैं। ऐसे में हास्यास्पद है कि कॉलेज प्रशासन ने एक बोर्ड लगा कर सभी को इमारत से दूर रहने की चेतावनी जारी कर रखी है। वे और करें भी क्या? जिस दिन कोई बड़ी दुर्घटना घटेगी राज्य का शिक्षा विभाग, जो स्वयं इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है, जांच का नाटक करने के लिए हाजिर हो जाएगा।

विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए जरूरी आधारभूत ढांचा होने तक के लिए आन्दोलन करना पड़ता है, इस त्रासदी का साक्षात नमूना फिलहाल फरीदाबाद के सबसे 'प्रतिष्ठित' सरकारी कॉलेज, सेक्टर 16ए स्थित नेहरू कॉलेज में देखने को मिलेगा। जबकि शिक्षा को समाज को सभ्य और परिपक्व बनाने का माध्यम होना चाहिए था।

कॉलेज गेट के बिल्कुल सामने एक शामियाने में कांग्रेस की छात्र विंग हरियाणा प्रदेश एनएसयूआइ के सचिव कृष्ण अत्री के नेतृत्व में छात्रों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन गत कई दिनों से जारी है। जिन आठ मांगों के साथ छात्रों ने ये धरना प्रारंभ किया उनकी जांच पड़ताल एक बेहद निराशाजनक परिदृश्य सामने लाती है।

पहली मांग है, सभी सरकारी कॉलेजों में यूजी/पीजी कक्षाओं में 20 प्रतिशत सीटें बढ़ाने की। छात्रों ने बताया कि इस मांग को लेकर एनएसयूआइ और भाजपा की एबीवीपी दोनों मोर्चा संभाले हुए हैं। मसला है कि हर साल यही मांग प्रमुखता से इन छात्र संगठनों द्वारा उठाई जाती है और हर



चेतावनी तो लिख कर टांग दी, खुद कब चेतोगे?

वर्ष सरकार द्वारा ये मान भी ली जाती है। अगले वर्ष बड़ी हुई सीटों को फिर से हटा लिया जाता है और एक बार फिर धरने का सिलसिला बन जाता है।

गौरतलब पहलू है कि राज्य में भाजपा सरकार होते हुए भी एबीवीपी किसे दिखाने के लिए प्रदर्शन कर रही है? की ही मांग वहीं एनएसयूआइ का सीटों को 20 प्रतिशत बढ़ाने की मांग सिर्फ एक साल के लिए करना भी हास्यास्पद है।

छात्र संघ चुनाव जो कि पिछले 22 वर्षों से नहीं हुए हैं, को प्रत्यक्ष रूप से कराने की बात भी एनएसयूआइ द्वारा उठाई गई है। वही आम छात्रों से बात करने पर उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। छात्र नहीं चाहते कि इस कैम्प

में दलगत राजनीति का आगमन इस रूप में हो जिससे उनकी क्लास में किसी प्रकार की बाधा पड़े।

फरीदाबाद में रीजनल सेंटर खुलवाने की मांग का समर्थन लगभग सभी छात्रों ने किया जिससे हर बार जो एमडीयू यूनिवर्सिटी रोहतक के चक्र काटने पड़ते हैं वो समाप्त हो जाए। छात्रों को लगता है कि प्रशासन इस मामले में बिल्कुल भी गंभीर नहीं जबकि ये कार्य तो एक छोटी सी बिल्डिंग में भी हो सकता है।

कृष्ण अत्री के अनुसार सेमेस्टर सिस्टम से पढाई की गुणवत्ता खराब हो रही है क्योंकि सभी शिक्षक सारा साल परीक्षा कराने में व्यस्त रहते हैं। जबकि आम छात्रों के अनुसार उनको इस सिस्टम से कोई



परेशानी नहीं बल्कि कुछ आसानी ही महसूस हो रही है। स्पष्ट नहीं कि फिर अत्री का संगठन इस सिस्टम को हटाने की मांग क्यों कर रहा है।

दरअसल, नेहरू कॉलेज क्या, तमाम कॉलेजों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। जहाँ एक ओर सरकार स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर शौचालय बनवाने की डींगें हांक रही है वहीं उच्च शिक्षण संस्थानों में इन सुविधाओं को लेकर छात्रों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है।

छात्रों की माने तो वो इन सब मांगों के साथ जब प्रिंसिपल से मिले तो उन्हें टाल दिया गया कि ये सब कार्य कर पाने के शक्तियां उनको प्राप्त नहीं हैं। इन्हीं मांगों को लेकर छात्र संगठन स्थानीय विधायक और खट्टर सरकार के प्रमुख मंत्री विपुल गौयल से भी 23 जुलाई को मिले थे जहाँ मंत्री ने मात्र दो दिन में निदान कर देने का जुमला चिपका सबको चलता किया। तब से लेकर आज तक इन मुद्दों पर सांस तक नहीं ले रहे मंत्री जी।

मुकेश अम्बानी के जिओ जैसे कागजी संस्थानों को 1000 करोड़ रुपये देने वाली मोदी सरकार जमीन पर कार्यरत शिक्षण संस्थानों को बर्बाद करने पर तुली है और हरियाणा में भाजपा की राज्य सरकार इसमें दो कदम आगे है। लगता है सरकारी संस्थान बर्बाद कर निजी और फर्जी संस्थानों को बढ़ावा दे कर अपनी जेबें भरना इनका एकमात्र उद्देश्य है जबकि युवा को वन्दे मातरम् में उलझा कर छोड़ दिया

गया है।

छात्र नेताओं में स्वयं स्पष्टता का आभाव दिखा। नेहरू कॉलेज में भी, शिक्षा का रोजगार से तालमेल न होने पर उनका जवाब दुल मुल ही रहा। जबकि कांवड यात्रा को आस्था बताने में कोई पीछे नहीं रहा। मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, अमित शाह कहते हैं हमने। करोड़ रोजगार दिया, मोदी कहते हैं आंकड़ा नहीं है, और गडकरी ने अंत में मोहर लगा दी कि रोजगार ही नहीं है। तो ये बेरोजगार भीड़ करेगी क्या?

कश्मीर घाटी में मिलिटेंटों की संख्या में पीएचडी और एमफिल तक के डिग्रीधारी शूमार हुए हैं इस वर्ष। वहीं उत्तर भारत में बेरोजगार भीड़ आतंक का पर्याय बन रही है, कभी गौरक्षक और कभी कावडिया के रोप में। अन्धविश्वास में डूबे नवयुवक राजनैतिक पार्टियों की वो पौध हैं जो आगे चल कर अन्धकार का वृक्ष बनेंगी और उसमें भरपूर योगदान सरकार का है।

शिक्षण संस्थानों को बर्बाद कर सरकारें भीड़ तंत्र में इजाफा करने को ही अंजाम देने में लगी हैं। नेहरू कॉलेज में विवश छात्रों ने बार-बार कहा कि हम कौन सा सरकार से रोजगार मांग रहे हैं, सिर्फ पढ़ने के लिए उचित व्यवस्था की ही तो मांग कर रहे हैं। यह स्थिति खट्टर सरकार के रोजगार प्रबंधन के खोखले दावों और विशेषकर शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा के दयनीय शिक्षा नेतृत्व को आईना दिखाने वाली है।

लीगल नोटिस में इज्जत तलाशता टंडन

फरीदाबाद (म.मो.) 18 जुलाई को वकील सुमित सिंह ने चैम्बर नम्बर 51 सैक्टर-12 फरीदाबाद कोर्ट के पते से अपने मुक्किल तनेन्द्र टंडन को सफेद पोश "देवता स्वरूप" बताते हुये इस अखबार के सहयोगी मनीश बतरा को 25 लाख रुपये का नोटिस भेजा। नोटिस में यह लिखा गया कि मनीश बतरा ने तनेन्द्र टंडन के लिये दिनांक 13-7-2018 को एक प्रेस-कॉन्फ्रेंस करी थी जिसमें मनीश बतरा ने "देवता स्वरूप" तनेन्द्र टंडन के लिये सही भाषा का प्रयोग नहीं किया व फेसबुक पर कॉन्फ्रेंस की खबर अपलोड करी जिससे तनेन्द्र की शौहरत को बढ़ा लगा है।

नोटिस में तनेन्द्र टंडन के स्वास्थ्य का भी जिक्र किया है कि उन्हें शूगर व बाईपास सर्जरी भी हुई पड़ी है। वकील सुमित ने इस नोटिस का जवाब अपनी फ्रीस 11000/- के साथ मांगा है। पाठकों को बता दें कि तनेन्द्र टंडन नाम के इस पुलिस दलाल के कर्म-कांडों का विवरण 'मजदूर मोर्चा' समय समय पर प्रकाशित करता रहा है। इसी क्रम में टंडन के कर्मकांडों का थोड़ा और विवरण नीचे दिया जा रहा है।

दिनांक 18-8-2014 को टंडन ने मनीश बतरा की दुकान पर बैठी एक महिला बैंककर्मी से एनआईटी के तत्कालीन एसीपी रामचंद्र राठी के नाम पर डेढ लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। महिला के खिलाफ थाना कोतवाली में एक झूठा मुकदमा दर्ज था जिसे

तफतीश के बाद तत्कालीन एसएचओ भरत सिंह ने खारिज कर दिया था। उस दौरान 'मजदूर मोर्चा' के संपादक सतीश कुमार भी इत्फाकन वहां थे। जिसको लेकर उन्होंने एसएचओ कोतवाली से बात की तो उन्होंने केस खारिज होने की पुष्टि करते हुये कहा कि किसी को एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। इस पर टंडन शर्मसार हुआ और अपना सा मुंह लेकर चला गया।

इसी तरह का एक दूसरा मामला एनएच 5 नम्बर, 5 एफ-42 ए में रहने वाली बुजुर्ग महिला अमृत कौर व उसके परिवार का है। इनके घर ग्राऊंड फ्लोर पर अमृत कौर से आये दिन झगड़ा करने के लिये टंडन ने सीमा व तान्या के परिवार को बिठा रखा है। टंडन वास्तव में इस पूरे मकान को हड़पने के लिये अमृत कौर व उसके परिवार को तरह-तरह से परेशान करता है।

दिनांक 1 जुलाई को थाना एनआईटी में 5 एन-17 ए में रहने वाली एक महिला के साथ मनोज नामक व्यक्ति ने बदतमीजी करी थी। जिसकी शिकायत महिला ने ब्लाकवासियों के साथ थाना एनआईटी में लिखित रूप में दी थी। जिसमें तनेन्द्र टंडन थाना एनआईटी पहुंच गये व पीड़ित परिवार को उनके ऊपर ही मामला दर्ज करवाने का दबाव बनाने लगे। जिसको लेकर पीड़ित परिवार ने समझौता कर लिया। उस समय तनेन्द्र टंडन ने मौका देखकर मनीष बतरा को थाना एनआईटी में धमकाते हुए शराब तस्करी व उसकी खबर प्रकाशित

करने के लिए धमकी दी और उसे जान से मारने की धमकी भी दी जिसकी एक लिखित शिकायत मनीष ने पुलिस कमिश्नर को दी भी हुई है। दिनांक 4 अक्टूबर 2017 को एनएच-5 नं. निवासी चरण ने एक शिकायत पत्र डीएसपी एनआईटी को दिया था कि एक ब्याजखोर उसे बयान के लिए तंग कर रहा है और धमका रहा है जिसकी जांच थाना एनआईटी प्रभारी मित्रपाल पर पहुंची। दिनांक 11 अक्टूबर 2017 से चरण को थाने में ब्याजखोर विपिन हलवाई, तनेन्द्र टंडन व थाना प्रभारी मिलकर शिकायत वापिस लेने का दबाव बनाते रहे हैं। अभी हाल ही में एनएच 5 के निवासी नरेन्द्र कुमार के साथ भी टंडन ने गुंडागर्दी करके उसका खोखा हटाने का प्रयास किया। यह व्यक्ति करीब 30 वर्षों से इस खोखे पर काबिज है। टंडन इसे बेदखल करके इस जगह पर अपना शराब का ठेका खोलना चाहता है। टंडन के गुंडों ने नरेन्द्र को काफ़ी धमकाया तथा विधायक सीमा त्रिखा का हवाला भी दिया। सीमा के कहने पर नगर निगम के दो कर्मचारी खोखा तोड़ने भी आ पहुंचे थे। नरेन्द्र ने जैसे-तैसे उनसे दो-चार दिन की मोहलत मांग कर न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त करके अपने आप को बचा लिया।

इस तरह का सफेदपोश गुंडे पालने वाला, पुलिस की दलाली करने वाला व शराब का तस्करी भला किसी समाज में इज्जतदार हो सकता है?



2008 में 2G स्पेक्ट्रम को
मनमोहन सरकार ने 11600 करोड़
के दर से बेचा था...

2018 में मोदी सरकार
5G स्पेक्ट्रम को 6200 करोड़ के दर
से बेच रही है..

उस समय कांग्रेस पर घोटाले का आरोप
लगाने वाले अब क्या कहेंगे?
अब कितने का घोटाला हो रहा है??